Writers Crew International Research Journal

ISSN: 3048-5

541Online

WRITERS CREW INTERNATIONAL RESEARCH

JOURNAL

हरियाणा के संदर्भ में उच्च शिक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी

डॉ. कमल पाण्डेय

डैबहैंड असाइनमेंट वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक

शैक्षिक सलाहकार

दिल्ली

Vol. 1, Issue: 9, November 2024

Writers Crew International Research Journal

ISSN: 3048-5

541Online

सारांश:

उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) एक महत्वपूर्ण अवधारणा है, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती है। PPP का उद्देश्य सार्वजनिक सेवाओं और संसाधनों में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करना है, जिससे बेहतर गुणवत्ता, संसाधनों का बेहतर उपयोग, और शिक्षा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा मिल सके। यह अवधारणा 1980 के दशक में पश्चिमी देशों में उभरी, जब निजी क्षेत्र ने उन क्षेत्रों में भी भूमिका निभानी शुरू की, जो पहले से ही सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकार क्षेत्र में थे। जबकि स्कूली शिक्षा में PPP का विश्लेषण और नीति निर्माण पहले से हो रहा है, उच्च शिक्षा में PPP पर बहुत कम ध्यान दिया गया है।

हरियाणा के संदर्भ में, उच्च शिक्षा में PPP का महत्व और उसकी भूमिका का अध्ययन किया जाना अत्यंत आवश्यक है। सरकारें पूर्ण निजीकरण के बजाय इस 'मध्य मार्ग' को अपनाते हुए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी कर सकती हैं, जिसमें निजी क्षेत्र द्वारा उच्च शिक्षा सेवाओं या उन

सेवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधनों की आपूर्ति की जा सकती है। इस संदर्भ में, दो महत्वपूर्ण अवधारणाएं उभरकर सामने आती हैं: पहला, निजी वित्त पहल (PFI), जो एक दीर्घकालिक अनुबंध है और निजी क्षेत्र की संपत्ति स्वामित्व से जुड़ा होता है। दूसरा, 'आउटसोर्सिंग' या 'फ्रैंचाइजिंग', जिसमें कुछ विशिष्ट संपत्ति निवेश निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है।

इस शोध पत्र का उद्देश्य हरियाणा राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में PPP की भूमिका, चुनौतियाँ और संभावनाओं का विश्लेषण करना है। साथ ही, यह अध्ययन PPP के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक नीति ढांचे और सुझावों को भी सामने रखेगा।

परिचय

सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) शब्द में कई तरह के अर्थ, तंत्र और नीतिगत उपकरण शामिल हैं। पीपीपी के किसी विशेष रूप को परिभाषित करने के लिए सार्वजनिक और निजी भागीदार के अर्थ, भूमिका, जिम्मेदारी और प्रोत्साहन को निर्दिष्ट करना होगा। पीपीपी चाहे

किसी भी रूप में हो, वैचारिक और व्यावहारिक रूप से, यह विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के वित्तपोषण और प्रावधान में निजी क्षेत्र के बढ़ते महत्व पर जोर देता है। पीपीपी शब्द का उदय 1980 के दशक में देखा जा सकता है, जब पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं में, निजी क्षेत्र उन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हो रहा था जो मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित थे। शिक्षा क्षेत्र ऐसा ही एक क्षेत्र है। जबकि स्कूली शिक्षा में पीपीपी एक अच्छी तरह से खोजा गया नीतिगत क्षेत्र है, उच्च शिक्षा में पीपीपी को अकादमिक साहित्य के साथ-साथ नीति निर्माण में भी बहुत कम ध्यान दिया गया है।[1]

निजी क्षेत्र के बढ़ते महत्व को देखते हुए, निजीकरण के लिए जाने के बजाय, सरकारें पीपीपी को अपनाने के मध्य मार्ग का सहारा लेना पसंद कर सकती हैं। इसका मतलब है कि निजी क्षेत्र के साथ अनुबंध करके उपभोक्ताओं को सेवाएँ प्रदान करना या इन सेवाओं के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण इनपुट प्रदान करना। इस संदर्भ में, दो शब्दावलियाँ महत्वपूर्ण हो जाती हैं - एक, निजी वित्त पहल (PFI), जो एक दीर्घकालिक अनुबंध है, जो आम तौर पर उन मामलों को संदर्भित करता है जहाँ निजी क्षेत्र के पास महत्वपूर्ण संपत्ति का स्वामित्व होता है। दूसरा, अनुबंध करना या फ्रैंचाइज़िंग, का अर्थ है निजी क्षेत्र द्वारा कुछ विशिष्ट संपत्ति निवेश।

Writers Crew International Research Journal

ISSN: 3048-5

541Online

---

1. यद्यपि उच्च शिक्षा के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण और अनुदान सहायता मॉडल के रूप में उच्च शिक्षा का निजी प्रावधान भारत में उत्तर-औपनिवेशिक उच्च शिक्षा प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है, लेकिन पीपीपी के नए रूपों, विशेष रूप से जहां निजी क्षेत्र आगे आता है और उच्च शिक्षा में निवेश करता है, पर सिद्धांत और व्यवहार में बहुत कम ध्यान दिया गया है।

2. ग्राउट, पॉल ए. और मार्गरिट स्टीवंस। "मूल्यांकन: सार्वजनिक सेवाओं का वित्तपोषण और प्रबंधन।" ऑक्सफोर्ड आर्थिक नीति की समीक्षा 19.2 (2003): 215-234।

पीपीपी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच एक सहजीवी संबंध है, जहां दोनों पक्ष निवेश की कमी के मुद्दों, आमतौर पर सामाजिक ओवरहेड्स और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में समाधान प्रदान करने के लिए एक-दूसरे के ज्ञान, संसाधनों, कौशल और विशेषज्ञता का इष्टतम उपयोग करने के लिए एक साथ आते हैं। हालांकि, पीपीपी क्या है, इसकी कोई एकल स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय परिभाषा नहीं है (पीपीआईएएफ, विश्व बैंक संस्थान 2012)। विभिन्न देशों में पीपीपी के विभिन्न सफल मॉडल देखे जा सकते हैं, जहां प्रत्येक मॉडल सार्वजनिक और निजी भूमिकाओं और क्षमताओं को अलग-अलग तरीके से जोड़ता है। यदि एक ओर, आयरलैंड का पीपीपी मॉडल एक गठबंधन का प्रस्ताव करता है, जहां 'सार्वजनिक क्षेत्र आवश्यक सेवा आउटपुट निर्दिष्ट करता है और निजी क्षेत्र उन्हें प्राप्त करने के लिए सर्वोत्तम साधन प्रस्तावित करता है' [4] जोखिम साझा करने पर पर्याप्त जोर देते हुए, दूसरी ओर यूनाइटेड

किंगडम का पीएफआई मॉडल सार्वजनिक सेवाओं को विकसित करने के लिए निजी वित्त का उपयोग करता है।

भारत में पी.पी.पी.

हालांकि, भारत में, एक अधिक सहयोगात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है, जहां सरकार या तो एक वित्त पोषण एजेंसी या सेवाओं की खरीदार की भूमिका निभा सकती है या एक समन्वयक या सुविधाकर्ता बन सकती है, जो उन क्षेत्रों को निर्दिष्ट करती है जहां निजी पहल की जानी चाहिए। [5] हालांकि भारत के आर्थिक इतिहास में सार्वजनिक निजी पहल के छिटपुट उदाहरण देखे जा सकते हैं, चाहे वह 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय "गारंटीकृत" रेलवे में ब्रिटिश कंपनियों द्वारा निवेश हो या 1910 में टाटा द्वारा टाटा हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कंपनी की स्थापना हो।

---

3. आयरलैंड राज्य प्राधिकरण [पीपीपी व्यवस्था] अधिनियम, 2002

4. सामाजिक क्षेत्र पर पीपीपी उपसमूह की रिपोर्ट: सार्वजनिक निजी भागीदारी; योजना आयोग, भारत सरकार, 2004

5. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हम यहां जो भी डेटा प्रस्तुत करते हैं, वह भारत में बुनियादी ढांचे में पीपीपी पर है।

Writers Crew International Research Journal

ISSN: 3048-5

541Online

हालांकि, सार्वजनिक निजी पहल पर प्रमुख नीतिगत जोर 1990 के दशक में दिया गया था, खासकर 1997 में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के व्यावसायीकरण पर विशेषज्ञ समूह की सिफारिशों पर बुनियादी ढांचा विकास वित्त कंपनी की स्थापना के साथ (चटर्जी, 2012)। तब से बुनियादी ढांचे में पीपीपी परियोजनाओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 1991-92 में 5 के मामूली आंकड़े से, पीपीपी परियोजनाओं की संख्या 2017-18 में तेजी से बढ़कर 8144 हो गई है (आर्थिक मामलों का विभाग, भारत सरकार, 2017) [7] हालांकि, अगर हम 1991-92 से 2017-18 तक पीपीपी में क्षेत्रवार रुझानों का बारीकी से विश्लेषण करते हैं, तो हमें पीपीपी परियोजनाओं के आवंटन और वितरण में कुछ चौंकाने वाले रुझान मिलते हैं।

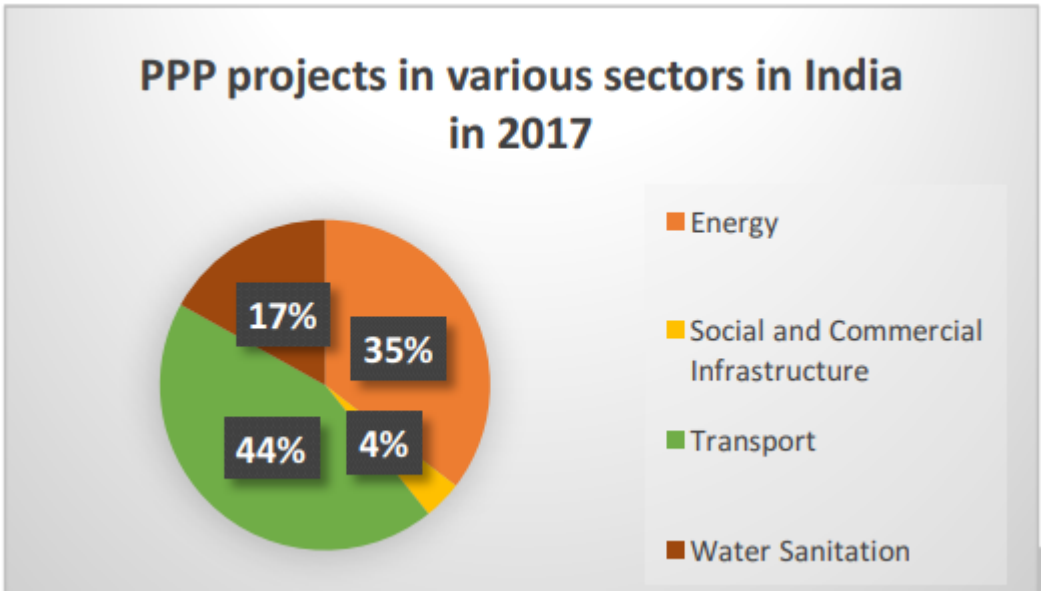

Writers Crew International Research Journal

ISSN: 3048-5

541Online

स्रोत: आर्थिक मामलों का विभाग, भारत सरकार[8]

परिवहन और ऊर्जा क्षेत्रों ने कुल पीपीपी परियोजनाओं में से 78 प्रतिशत को आकर्षित किया, जबकि सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे में पीपीपी की उपस्थिति मात्र 4 प्रतिशत है। सामाजिक और वाणिज्यिक बुनियादी ढांचे के भीतर लगभग 90 प्रतिशत निवेश सामान्य बुनियादी ढांचे और एसईजेड में चला गया है, जबकि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे सामाजिक क्षेत्रों में काफी कमी रह गई है। विशेष रूप से शिक्षा को लगभग नजरअंदाज कर दिया गया है, जिसमें निवेश का मात्र 0.48% ही प्राप्त हुआ है।

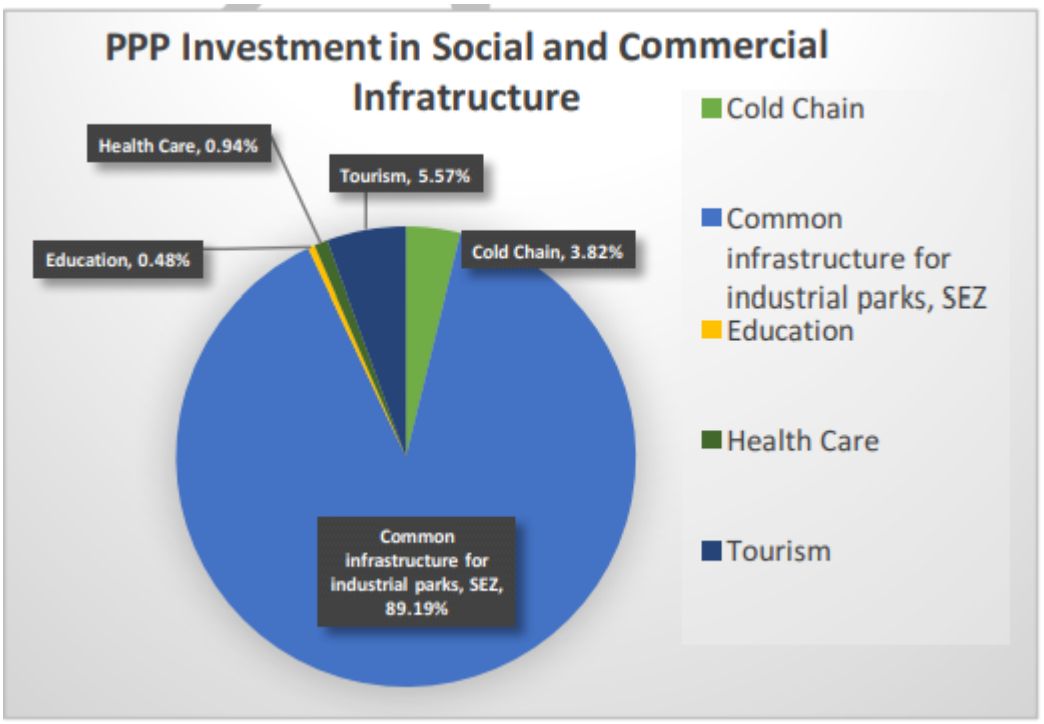

स्रोत: आर्थिक मामलों का विभाग, भारत सरकार[9]

हरियाणा भारत के सबसे अमीर राज्यों में से एक होने के बावजूद पीपीपी के लिए पसंदीदा जगह नहीं लगता है। पीपीपी परियोजनाओं की संख्या के मामले में हरियाणा झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों से पीछे है।

---

6. Infrastructureindia.gov.in, आर्थिक मामलों का विभाग, भारत सरकार, 2017.

https://infrastructureindia.gov.in/year-wise

7. अफरीदी, एम. (2018)। शिक्षा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी में समानता और गुणवत्ता: पंजाब, पाकिस्तान में विश्व बैंक समर्थित पीपीपी का एक अध्ययन (ऑक्सफैम रिसर्च रिपोर्ट)। ऑक्सफैम।

8. एंटोनिनिस, एम., और यूनेस्को (संपादक)। (2017)। शिक्षा में जवाबदेही: हमारी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना (दूसरा संस्करण)।

भारत में पीपीपी परियोजनाओं का राज्यवार आवंटन (1991-2017)

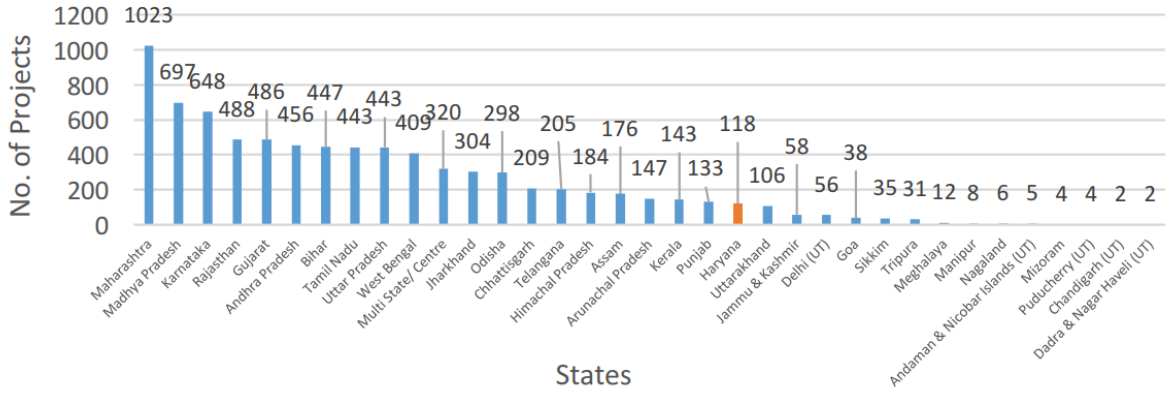

स्रोत: आर्थिक मामलों का विभाग, भारत सरकार10

हरियाणा में पीपीपी परियोजनाओं के क्षेत्रवार आवंटन के अनुसार, परिवहन पीपीपी के लिए सबसे अधिक मांग वाला क्षेत्र बनकर उभरा है।

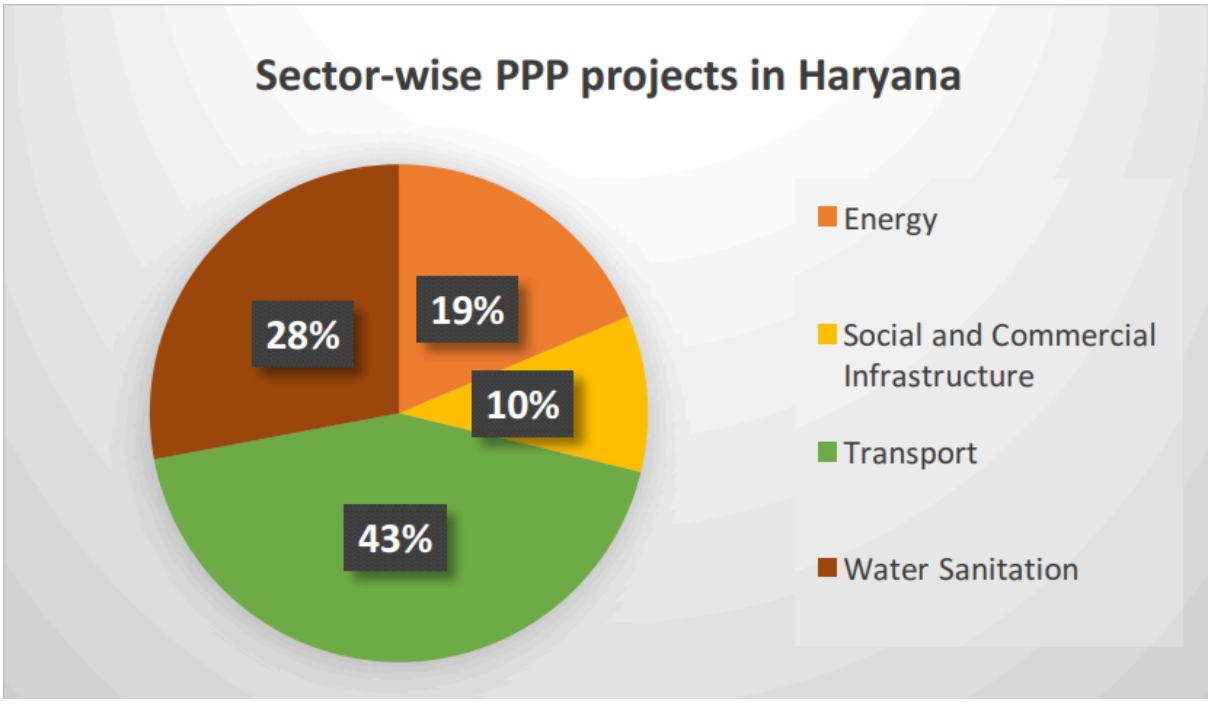

स्रोत: आर्थिक मामलों का विभाग, भारत सरकार11

परिवहन और जल स्वच्छता चैंपियन क्षेत्र के रूप में उभरे हैं, जो 71 प्रतिशत निवेश आकर्षित करते हैं, जबकि सामाजिक और वाणिज्यिक क्षेत्र बहुत पीछे रह गए हैं। सबसे परेशान करने वाली विशेषताओं में से एक सार्वजनिक निजी निवेश के प्राप्तकर्ता के रूप में शिक्षा क्षेत्र की अनुपस्थिति है। हरियाणा में पीपीपी को उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने, भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढांचे की परिसंपत्तियों के विकास और संवर्द्धन के साथ-साथ मौजूदा लोगों के प्रबंधन और राज्य के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार के

लिए निजी क्षेत्र की सुविधा के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के साधन के रूप में देखा जाता है (हरियाणा में पीपीपी नीति, हरियाणा सरकार)। हरियाणा में निजी निवेश को नीतिगत जोर देने के लिए, राज्य के वित्त विभाग में पीपीपी सेल की स्थापना की गई थी।

परिवहन और जल स्वच्छता चैंपियन क्षेत्र के रूप में उभरे हैं, जो 71 प्रतिशत निवेश आकर्षित करते हैं, जबकि सामाजिक और वाणिज्यिक क्षेत्र बहुत पीछे रह गए हैं। सबसे अधिक परेशान करने वाली विशेषताओं में से एक सार्वजनिक निजी निवेश के प्राप्तकर्ता के रूप में शिक्षा क्षेत्र की अनुपस्थिति है। हरियाणा में पीपीपी को उच्च गुणवत्ता वाली सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने, भौतिक और सामाजिक बुनियादी ढाँचा परिसंपत्तियों के विकास और संवर्द्धन के साथ-साथ मौजूदा लोगों के प्रबंधन और राज्य के लोगों के जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार के लिए निजी क्षेत्र की सुविधा के लिए एक सक्षम वातावरण बनाने के साधन के रूप में देखा जाता है (हरियाणा में पीपीपी नीति, हरियाणा सरकार)। हरियाणा में निजी निवेश को नीतिगत जोर देने के लिए, 'राज्य वित्त विभाग में पीपीपी सेल की स्थापना सरकार को क्षमता वृद्धि/विकास के माध्यम से केंद्रीय और राज्य स्तर पर पीपीपी को मुख्यधारा में लाने में सहायता करने के लिए

की गई थी।' (हरियाणा सरकार, 2010) हरियाणा की पीपीपी नीति ने कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों और उप-क्षेत्रों को बढ़ावा दिया है जहाँ वे चाहते हैं कि निजी निवेश आगे आए। इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, पर्यटन एवं संबंधित परियोजनाएं, शहरी बुनियादी ढांचा, बिजली, राजमार्ग, सड़क परिवहन प्रणाली, नागरिक उड्डयन, औद्योगिक बुनियादी ढांचा, ग्रामीण-सार्वजनिक सुविधाएं और ई-गवर्नेंस शामिल हैं। (पीपीपी नीति, हरियाणा सरकार) पूरी तरह कार्यात्मक पीपीपी सेल और निर्धारित दिशा-निर्देशों और अधिदेश के साथ एक पीपीपी नीति के बावजूद, हम देखते हैं कि हरियाणा में निवेश बहुत अधिक नहीं हो रहा है। यदि हम रुझानों पर बारीकी से नज़र डालें, तो हम पाते हैं कि हरियाणा भारतीय राज्यों में सबसे निचले पायदान पर है। हालांकि यह तर्क दिया जा सकता है कि क्षेत्र का भौगोलिक आकार और आर्थिक विकास निवेश को आकर्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे हरियाणा के कुछ पड़ोसी राज्यों का बेहतर प्रदर्शन दर्शाता है कि हरियाणा अपनी क्षमता का सही उपयोग नहीं कर रहा है। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा में सार्वजनिक निजी निवेश का लगभग अभाव चिंता का विषय है, जिसकी जड़ों और कारणों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हम सबसे पहले उच्च शिक्षा में पीपीपी की अवधारणा का विश्लेषण करके

शुरुआत करेंगे। विशेष रूप से, हम उच्च शिक्षा में पीपीपी की आवश्यकता के कारणों, इसके संभावित रूपों का पता लगाएंगे और फिर हरियाणा के लिए कुछ नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत करेंगे।

निजी क्षेत्र और उच्च शिक्षा

वैचारिक स्तर पर, उच्च शिक्षा में पीपीपी भागीदारी के लिए इस क्षेत्र में निजी खिलाड़ियों की मौजूदगी की आवश्यकता होगी। नीतिगत स्तर पर, इसके लिए अनुकूल विनियामक वातावरण की आवश्यकता होगी जो उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र के अस्तित्व और भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। यहाँ, निजी क्षेत्र का अर्थ केवल लाभ कमाने वाले व्यावसायिक उद्यम ही नहीं बल्कि गैर-लाभकारी संगठन, निजी विश्वविद्यालय, समुदाय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दाता एजेंसियाँ आदि भी हैं। उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी कोई नई घटना नहीं है। ऐतिहासिक रूप से, समाज में निजी संस्थाएँ मौजूद रही हैं। 15वीं शताब्दी की अंतिम तिमाही में, यूरोपीय लोगों ने भारत के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया था। उन्होंने और निजी ईसाई मिशनरियों ने शिक्षण संस्थानों की स्थापना करके अपने धर्म और पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करना शुरू किया। भारत

में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन ने इस दिशा में और अधिक ठोस विकास किया। 1857 में, 1854 के वुड के डिस्पैच के बाद, निजी और मिशनरी मदद से जन शिक्षा की आवश्यकता को पहचाना गया। इससे विकेंद्रीकरण भी हुआ - प्रत्येक प्रांत में शिक्षा के प्रशासन के लिए अलग विभाग का निर्माण, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के पहले तीन विश्वविद्यालयों की स्थापना और अनुदान सहायता की प्रणाली की शुरुआत। दिलचस्प बात यह है कि इन विश्वविद्यालयों ने शिक्षण की जिम्मेदारी नहीं ली और प्रशासन तक ही सीमित रहे। उनके अधिकांश खर्च छात्रों द्वारा दी जाने वाली फीस से पूरे होते थे। इन विश्वविद्यालयों से कई कॉलेज संबद्ध थे। इस प्रकार, विश्वविद्यालयों का अपना बौद्धिक जीवन बहुत कम था और वे बड़े पैमाने पर लंदन विश्वविद्यालय (जयराम, 2004) की तर्ज पर संबद्ध और परीक्षा निकाय बने रहे। इनके अलावा, इस अवधि में ब्रह्मो समाज जैसे कई गैर-मिशनरी संगठन थे जो भारत में यूरोपीय शिक्षा का प्रचार करते थे। इनमें से कई शैक्षणिक संस्थानों को सरकार द्वारा शैक्षिक अनुदान, दान और छात्र शुल्क (जयपालन, 2005) द्वारा वित्त पोषित किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय दोनों ही निजी, धार्मिक संस्थानों के रूप में शुरू हुए और उन्हें रियासतों के शासकों से बड़े पैमाने पर दान मिला (पोवार और भल्ला, 2008)। वे स्वतंत्रता के

बाद ही सरकारी फंडिंग पर अधिक निर्भर हो गए। फंडिंग एजेंसियों के उद्देश्यों ने शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता को बाधित किया। उदाहरण के लिए, 1835 में ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अनुसार, सरकार के पास उपलब्ध सभी फंड अंग्रेजी शिक्षा पर खर्च किए जाने चाहिए, जो कि स्थानीय भाषा के माध्यम से शिक्षण के पक्ष में ओरिएंटलिस्ट रुख के खिलाफ आंग्लवादियों का समर्थन करता है। स्वतंत्रता के बाद, यह महसूस किया गया कि भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली औपनिवेशिक विरासत से प्रभावित है और इसे एक स्वतंत्र देश के उद्देश्यों के अनुसार सुधारना होगा। यह बताया गया है कि स्वतंत्रता के बाद, 1990 के दशक की शुरुआत में संरचनात्मक समायोजन योजनाओं को अपनाने के बाद ही उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की अधिक भूमिका के लिए भारतीय सरकार द्वारा समर्थन किया गया था (तिलक, 2005)। इससे पहले, किसी भी नीति दस्तावेज़ ने निजी क्षेत्र की बढ़ी हुई भूमिका का समर्थन नहीं किया था (जीओआई, 1966; 1968; 1986)। हालाँकि, इनमें से कई दस्तावेज़ बहुत अधिक कैपिटेशन फ़ीस वसूलने वाले तकनीकी कॉलेजों के बढ़ते व्यावसायीकरण के बारे में संदेहास्पद थे (जीओआई, 1985, 1986 तिलक, 2005 में उद्धृत)। स्वतंत्रता के बाद से, भारतीय उच्च शिक्षा क्षेत्र की नियमित विशेषताएँ राज्य द्वारा वित्तपोषित निजी कॉलेज हैं, जिनमें राज्य अनुदान के माध्यम से

Writers Crew International Research Journal

ISSN: 3048-5

541Online

मूल्य नियंत्रण और लागत अंडरराइटिंग है। इसे भारत में अनुदान-सहायता (जीआईए) प्रणाली के रूप में भी जाना जाता है। कुछ लोग तर्क देते हैं कि यह 'छद्म निजीकरण' है क्योंकि निजी कॉलेजों के हाथों में बहुत कम स्वायत्तता बची है। विभिन्न सरकारी कॉलेजों का भी निजीकरण हुआ है। उदाहरण के लिए, 1997 में मध्य प्रदेश सरकार ने छह मेडिकल कॉलेजों और इसके अस्पतालों को गैर-लाभकारी स्वायत्त ट्रस्टों को हस्तांतरित कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि सबसे अधिक दिखाई देने वाला परिवर्तन इन मेडिकल कॉलेजों की फीस में 600 रुपये से 12000 रुपये प्रति माह की वृद्धि थी (ibid)। उच्च शिक्षा की अपूर्ण मांग को पूरा करने के लिए भारत में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में वृद्धि हुई है। हाल के वर्षों में निजी उच्च शिक्षा संस्थानों में यह वृद्धि महत्वपूर्ण रही है। जब विश्वविद्यालय शिक्षा की बात आती है, तो लगभग 35% विश्वविद्यालय निजी तौर पर प्रबंधित होते हैं। हालांकि, जब निजी तौर पर प्रबंधित कॉलेजों की बात आती है, तो भारत के कुल कॉलेजों में से लगभग 78% निजी तौर पर प्रबंधित होते हैं। स्टैंड-अलोन संस्थानों का प्रबंधन मुख्य रूप से निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है (लगभग 76%)।

उच्च शिक्षा में सार्वजनिक निजी भागीदारी

Writers Crew International Research Journal

ISSN: 3048-5

541Online

उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र के बढ़ते महत्व को कई कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है:

क) सार्वजनिक व्यय में कमी: भारत अपने सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3% शिक्षा क्षेत्र पर खर्च करता है। यह कई नीति दस्तावेजों में प्रस्तावित 6% से कम है। पिछले कुछ वर्षों में, वास्तविक रूप से, उच्च शिक्षा पर बजटीय आवंटन में थोड़ी वृद्धि हुई है। वास्तव में, उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा संसाधनों के सृजन की दिशा में एक कदम उठाया गया है। RUSA के अनुसार, संस्थानों को संसाधन उत्पन्न करने के लिए बाध्य किया जाता है और इसे संस्थागत विकास योजना का एक रणनीतिक हिस्सा बनाना चाहिए। संस्थागत संसाधन सृजन के लिए विश्वविद्यालय के संसाधनों के वाणिज्यिक उपयोग की आवश्यकता होगी। इसमें निजी क्षेत्र के संगठनों के साथ भागीदारी शामिल हो सकती है।

जबकि उच्च शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के महत्व को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, संसाधन सृजन और दान में निजी क्षेत्र का योगदान तेजी से महत्वपूर्ण होता जा रहा है।

ख) उच्च शिक्षा में सरकार की विफलता: यद्यपि भारत के संदर्भ में सार्वजनिक उच्च शिक्षा के महत्व को कम नहीं किया जा सकता है, लेकिन सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली की बढ़ती अक्षमता

गंभीर चिंता का विषय है। जबकि सार्वजनिक उच्च शिक्षा उच्च शिक्षा में छात्रों के नामांकन का बहुमत प्रदान करती है, अधिकांश सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थान, विशेष रूप से कॉलेज, शिक्षकों की खराब गुणवत्ता, शिक्षकों की अनुपस्थिति, खराब बुनियादी ढांचे, पुराने पाठ्यक्रम, अनुकूल शासन प्रणाली और अनुसंधान वातावरण की कमी से ग्रस्त हैं। अर्थशास्त्र साहित्य में, सरकारी क्षेत्र के संगठनों की विफलता को अक्सर गलत तरीके से प्रेरित प्रोत्साहन संरचना के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है जो शिक्षा प्रदाताओं के रवैये में सुस्ती को बढ़ावा देता है। यह किसी समस्या के किसी भी रचनात्मक समाधान की खोज की संभावना को बाधित करता है, जिससे उच्च शिक्षा की समग्र गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों के भीतर भी निजी क्षेत्र की भागीदारी की आवश्यकता है।

ग) सार्वजनिक नीति में बाजार और बाजार जैसे तंत्र का बढ़ता महत्व: उपरोक्त चर्चा के संबंध में, उच्च शिक्षा में बाजार और बाजार जैसे तंत्र का बढ़ता महत्व रहा है। बाजार के आर्थिक सिद्धांत का हवाला देते हुए, यह तर्क दिया जाता है कि बाजार की सेटिंग में संस्थान अपने ग्राहकों की मांग को पूरा करेंगे और इस प्रकार उन्हें सर्वोत्तम मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु प्रदान

करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है (लागतों को अनुकूलित करके)। यह उत्पादकता के साथ-साथ दक्षता को भी प्रोत्साहित करेगा। इस प्रकार, कई नीति निर्माता उच्च शिक्षा में एक बाजार के उद्भव का तर्क देते हैं जिसमें निजी संस्थानों का उदय भी शामिल है। यह सार्वजनिक उच्च शिक्षा संस्थानों में बाजार जैसे तंत्र की शुरूआत को भी प्रोत्साहित करता है। जबकि उच्च शिक्षा के बड़े सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सार्वजनिक संस्थानों के महत्व को महसूस किया जाता है, संकाय प्रदर्शन पर जोर देने या पाठ्यक्रमों के चयन को प्रोत्साहित करने जैसे बाजार जैसे तंत्रों को स्थापित करना, छात्र संतुष्टि के साथ-साथ संकाय उत्पादकता में सुधार करने का प्रयास है।

d) निजी परोपकार को चैनलाइज़ करना: निजी परोपकार ने भारत में उच्च शिक्षा में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उच्च शिक्षा में निजी परोपकार के शुरुआती उदाहरण स्वतंत्रता-पूर्व काल (1892-1947) में हैं (मेहता और कपूर, 2004)। 'इस अवधि में भारत के कुछ सबसे स्थायी ट्रस्ट और फाउंडेशन और स्थायी महत्व के सार्वजनिक संस्थान - अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया इस्लामिया, अन्नामलाई विश्वविद्यालय, भारतीय

विज्ञान संस्थान, अन्य - की स्थापना बड़े पैमाने पर स्वैच्छिक दान के माध्यम से की गई थी।' (ibid, 26)। इस अवधि में स्थापित कुछ प्रमुख ट्रस्ट टाटा (सर रतन टाटा, सर दोराबजी टाटा और जेआरडी टाटा), बजाज, बिड़ला (जी.डी. बिड़ला, बी.एम. बिड़ला), लालभाई, साराभाई, गोदरेज, श्री राम, सिंघानिया, मोदी, अन्नामलाई चेट्टियार, मुरुगप्पा समूह (एएएम फाउंडेशन), नायडू, रामको, मफतलाल और महिंद्रा थे। इन ट्रस्टों ने भारत में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाई। दिलचस्प बात यह है कि इन परोपकारी अनुदानों का एक बड़ा हिस्सा भारत में सार्वजनिक संस्थानों का समर्थन करता है। लगभग उसी समय भारत में प्रथम श्रेणी के निजी संस्थान भी स्थापित किए गए थे - उदाहरण के लिए, भारतीय विज्ञान संस्थान (IISC), बैंगलोर; टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च (TIFR), मुंबई; और बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (BITS), पिलानी, कुछ नाम हैं। स्वतंत्रता के बाद से, हालांकि निजी क्षेत्र में वृद्धि हुई है, यह देखना चौंकाने वाला है कि निजी परोपकार में कमी आई है (ibid)। हाल ही में उच्च शिक्षा में निजी परोपकार में उछाल आया है, सार्वजनिक संस्थानों को दान के रूप में नहीं बल्कि निजी उच्च शिक्षा संस्थानों के रूप में। इसलिए, उच्च शिक्षा में निजी परोपकार का अच्छा उपयोग करना उचित है।

Writers Crew International Research Journal

ISSN: 3048-5

541Online

उच्च शिक्षा संस्थानों के वित्तपोषण के लिए अवसंरचना कोष की स्थापना:

यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन पहला और सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां पीपीपी की आवश्यकता है, वह है कॉलेज का बुनियादी ढांचा। विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने से पहले, हमें सबसे पहले अपने मौजूदा कॉलेजों को बुनियादी टिकाऊ बुनियादी ढांचा प्रदान करने की आवश्यकता है। बहुत से कॉलेजों में बुनियादी ढांचा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। कई मामलों में, कॉलेजों के पास अपनी इमारतें और सुविधाएं नहीं हैं और वे अन्य स्कूलों और कॉलेजों में किराए के क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे हैं। इसके लिए बुनियादी ढांचे के लिए धन का प्रवाह आवश्यक है। इसलिए, निजी निवेश, विशेषज्ञता और सरकारी संसाधनों और जोखिम उठाने को मिलाकर, एक विशेष निजी साधन स्थापित किया जा सकता है जो हरियाणा में उच्च शिक्षा में बुनियादी ढांचा विकास निधि प्रदान करने/पुनर्वित्त करने में विशेषज्ञता हासिल करेगा। यह एजेंसी केवल उच्च शिक्षा में बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक अग्रणी एजेंसी के रूप में कार्य कर सकती है।

पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम विकास में सार्वजनिक निजी भागीदारी:

Writers Crew International Research Journal

ISSN: 3048-5

541Online

एक महत्वपूर्ण क्षेत्र जहां निजी पहल स्थायी योगदान दे सकती है, वह है हरियाणा में राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम विकास।

चूंकि उच्च शिक्षा का एक बड़ा मिशन युवाओं को नौकरी बाजार की मांगों और आवश्यकताओं के लिए तैयार करना और उन्हें महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने में मदद करना है, इसलिए यह जरूरी है कि पाठ्यक्रम और पाठ्यक्रम को इस तरह से संरचित किया जाए कि यह उद्योग और नौकरी बाजार की मांगों को पूरा करे।

यहां, सरकार, निजी व्यावसायिक कंपनियां, विश्वविद्यालय और अन्य एजेंसियां सभी इसमें योगदान दे सकती हैं। जबकि निजी व्यवसाय व्यावहारिक और औद्योगिक प्रशिक्षण और इंटर्नशिप पर पर्याप्त जोर देने के साथ वाणिज्य, प्रबंधन पाठ्यक्रम मॉड्यूल और पाठ्यक्रम विकसित करने में मदद कर सकते हैं, निजी विश्वविद्यालय सार्वजनिक कॉलेजों में शोध संस्कृति विकसित करने में मदद कर सकते हैं। एस्कॉर्ट्स ग्रुप, अवंता ग्रुप, एसआरएस ग्रुप और जिंदल ग्रुप जैसे कॉर्पोरेट घराने इस प्रयास में बड़े पैमाने पर योगदान दे सकते हैं। भारत की अग्रणी इंजीनियरिंग कंपनी एस्कॉर्ट, जीजेयूएसटी और दीन बंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

विश्वविद्यालय जैसे विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर ऐसे प्रोजेक्ट, प्रशिक्षण और पाठ्यक्रम विकसित कर सकती है, जो छात्रों को इंजीनियरिंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अत्याधुनिक शोध और नवीनतम तकनीकों से परिचित कराएंगे। इसी तरह, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी और अशोका यूनिवर्सिटी जैसे विश्वविद्यालय राज्य के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के साथ ज्ञान साझेदारी बना सकते हैं, जिसके तहत वे कानून, सामाजिक विज्ञान, कला और मानविकी में शोध की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक संस्थानों के साथ सहयोग कर सकते हैं।

छात्रों को मौद्रिक और गैर-मौद्रिक सहायता:

छात्रवृत्ति और वित्तीय सहायता कार्यक्रम विकसित किए जा सकते हैं, जिसके तहत निजी क्षेत्र वंचित पृष्ठभूमि से चयनित छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर सकता है। सीएसआर फंडिंग और निजी परोपकार इन क्षेत्रों में फंडिंग का एक उपयोगी स्रोत हो सकते हैं। उत्कृष्ट परोपकारी लोगों, व्यावसायिक हस्तियों और कॉर्पोरेट घरानों के प्रमुखों के नाम पर छात्रवृत्ति और वित्तीय

सहायता छात्रों को सालाना दी जा सकती है। उन छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए निजी प्रायोजन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों से विदेश में अध्ययन करना चाहते हैं। सरकार के सहयोग से स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए फेलोशिप कार्यक्रम विकसित किए जा सकते हैं। अशोका और ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी जैसे निजी विश्वविद्यालय फंडिंग को चैनलाइज़ करने और छात्रों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग और छात्रवृत्ति के बारे में उपयोगी जानकारी देने में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। ये विश्वविद्यालय छात्रों के लिए तीन से चार सप्ताह के ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन विद्यालय विकसित कर सकते हैं, जहाँ छात्रों को विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचे, नवीन शिक्षण विधियों, वैश्विक नेताओं और आलोचनात्मक विचारकों से परिचित कराया जाएगा, ताकि वे अकादमिक रूप से वैश्विक दृष्टिकोण विकसित कर सकें।

उच्च शिक्षा के विकास में सार्वजनिक-निजी भागीदारी:

एक ऐसा क्षेत्र जो बड़े पैमाने पर निजी कार्रवाई और पहल से रहित है, वह है सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं में निजी भागीदारी। हरियाणा जैसे आर्थिक रूप से समृद्ध राज्य में महिलाओं के

खिलाफ़ गंभीर लैंगिक भेदभाव है। यह सामाजिक पूर्वाग्रह उच्च शिक्षा में काफी हद तक मौजूद है। नूंह और फतेहाबाद जैसे कुछ जिलों में, महिला सकल नामांकन अनुपात एकल अंक में है, जो उच्च शिक्षा के लिए चिंताजनक तस्वीर पेश करता है। यहाँ, निजी क्षेत्र सामाजिक परिवर्तन के सूत्रधार के रूप में आगे आ सकता है। वे जमीनी स्तर पर शामिल हो सकते हैं और अभियानों, अभिभावकों के साथ जुड़ाव, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम करने वाले फाउंडेशनों को प्रायोजित करने और सामुदायिक जुड़ाव पहलों को प्रोत्साहित करने और उनमें भाग लेने के माध्यम से लैंगिक भेदभाव के खिलाफ़ अभियानों को बढ़ावा देने में निवेश कर सकते हैं।

गैर सरकारी संगठनों, समुदायों और परिवारों जैसे अन्य गैर-राज्य अभिनेताओं को शामिल करना

पीपीपी में निजी के विचार को गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है, जिनके पास उच्च शिक्षा के बड़े सामाजिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ज्ञान, विशेषज्ञता और अन्य उपयोगी संसाधन (गैर-मौद्रिक) हैं। लिंग संवेदनशीलता से लेकर कानून जैसे पाठ्यक्रमों में नैदानिक कार्यक्रमों तक, गैर सरकारी संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उच्च शिक्षा विकास में समुदायों और परिवारों जैसे अन्य गैर-राज्य अभिनेताओं को शामिल

करने के लिए एक नीति रूपरेखा तैयार की जा सकती है। समुदायों और परिवारों के साथ मिलकर काम करते हुए, उच्च शिक्षा संस्थान समुदायों और परिवारों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों को समझ सकते हैं और उनका समाधान कर सकते हैं।

सहभागी अनुसंधान के विचार को शामिल करने के लिए ज्ञानमीमांसा ज्ञान का और अधिक पता लगाया जाना चाहिए।

हालांकि, इसके लिए बुनियादी नीतिगत बुनियादी ढांचे की स्थापना के साथ-साथ विश्वविद्यालय के लिए अपने तत्काल समुदाय के साथ सहयोग करने के लिए अच्छी तरह से डिज़ाइन किए गए प्रोत्साहन की आवश्यकता होगी।

डेटा संग्रह और विश्लेषण

तालिका 1: हरियाणा में उच्च शिक्षा संस्थानों की PPP मोड पर स्थिति (2024 तक)

क्रम संख्या	संस्थान का नाम	स्थापना वर्ष	PPP मोड की श्रेणी	प्रमुख निजी साझेदार	छात्र संख्या	प्रमुख पाठ्यक्रम	PPP से मिलने वाले लाभ
1	हरियाणा टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी	2001	निजी वित्त पहल (PFI)	ABC ग्रुप	10,000	इंजीनियरिंग, प्रबंधन	उच्च गुणवत्ता की सुविधाएं, वित्तीय निवेश

2	XYZ मेडिकल कॉलेज	2005	आउटसोर्सिंग	XYZ हेल्थकेयर	5,000	मेडिकल शिक्षा	बेहतर इन्फ्रास्ट्रक्चर और आधुनिक उपकरण
3	ABC इंजीनियरिंग कॉलेज	2010	फ्रैंचाइजिंग	PQR कॉर्पोरेशन	7,500	इंजीनियरिंग	नई पाठ्यक्रम संरचनाएँ, उद्योग-सहयोग

डेटा व्याख्या: इस तालिका से पता चलता है कि हरियाणा में उच्च शिक्षा संस्थानों में PPP के तहत निजी निवेश का महत्व बढ़ रहा है। निजी साझेदारों के साथ सहयोग से बेहतर सुविधाएं और आधुनिक शिक्षा प्रदान की जा रही है।

तालिका 2: PPP मोड द्वारा हरियाणा में उच्च शिक्षा की चुनौतियाँ (सर्वेक्षण परिणाम)

चुनौती	PPP संस्थानों की संख्या	संस्थानों का प्रतिशत (%)
सरकारी निधि की कमी	20	50%
निजी साझेदारों का अपर्याप्त योगदान	12	30%
शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने की कठिनाई	10	25%
कानूनी एवं नीति संबंधित समस्याएं	8	20%

Writers Crew International Research Journal

ISSN: 3048-5

541Online

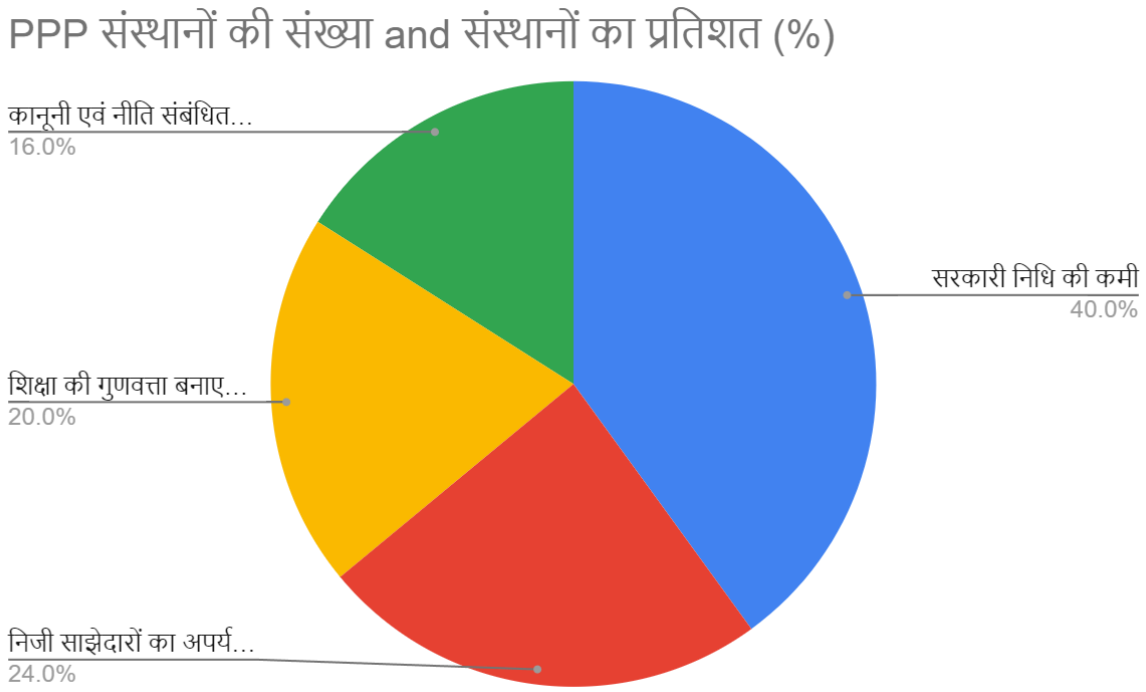

डेटा व्याख्या: सर्वेक्षण के अनुसार, 50% संस्थानों ने सरकारी निधि की कमी को प्रमुख चुनौती के रूप में बताया, जबकि 30% संस्थानों ने निजी साझेदारों के योगदान में कमी की बात कही। शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखना और कानूनी समस्याएं भी प्रमुख चुनौतियाँ हैं।

तालिका 3: PPP मोड के माध्यम से उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय निवेश का विश्लेषण (2021-2024)

Writers Crew International Research Journal

ISSN: 3048-5

541Online

वर्ष	सरकारी निवेश (करोड़ रु.)	निजी निवेश (करोड़ रु.)	PPP मॉडल के तहत कुल निवेश (करोड़ रु.)
2021	500	300	800
2022	600	350	950
2023	550	400	950
2024	700	450	1,150

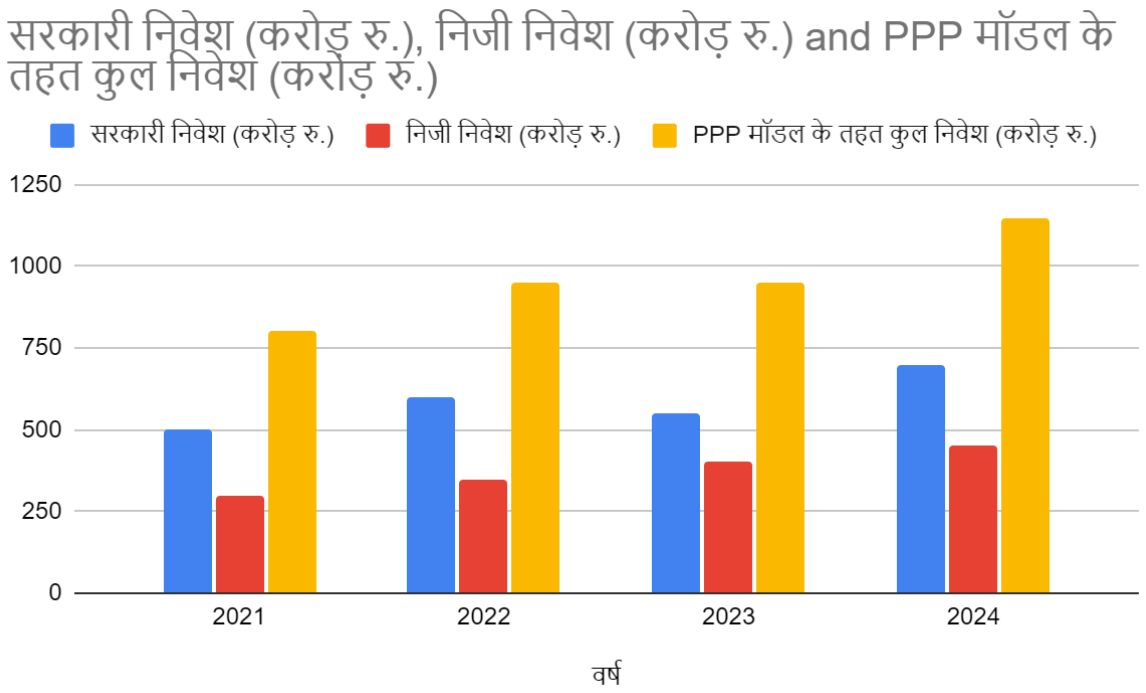

डेटा व्याख्या: वर्ष 2021 से 2024 तक PPP मोड के तहत उच्च शिक्षा में सरकारी और निजी निवेश दोनों में वृद्धि देखी गई है। 2024 में कुल निवेश 1,150 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि PPP मॉडल उच्च शिक्षा में आर्थिक विकास का प्रमुख साधन बन रहा है।

निष्कर्ष

उच्च शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए भागीदारों की समिति बनाने की आवश्यकता है। सरकारी कॉलेजों के साथ मिलकर काम करने के लिए व्यक्तियों, कॉर्पोरेट, गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्टों/सोसायटियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक उपयुक्त नीति विकसित की जानी चाहिए। संभावित निजी क्षेत्र के भागीदारों को संवेदनशील बनाने के लिए कॉलेजों में नियमित कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। स्थानीय भागीदारों को आमंत्रित करने पर जोर दिया जाना चाहिए जो कॉलेजों को प्रायोजित कर सकते हैं।

उच्च शिक्षा में पीपीपी के विचार पर नीति निर्माताओं को अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि, नए रूपों, अभिनेताओं (सार्वजनिक-केंद्र, राज्य और स्थानीय, और निजी-उद्योग, निजी विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, समुदाय आदि), तंत्र (अनुबंध के साथ-साथ निजी वित्त पहल), उपकरण और अनुबंध की शर्तों की अवधारणा और कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा नीति में नई सोच को अपनाने का समय आ गया है और उच्च शिक्षा में पीपीपी में नए रूपों की खोज करना सही दिशा में एक कदम होगा।

संदर्भ सूची

1. यद्यपि उच्च शिक्षा के लिए सार्वजनिक वित्त पोषण और अनुदान सहायता मॉडल के रूप में उच्च शिक्षा का निजी प्रावधान भारत में उत्तर-औपनिवेशिक उच्च शिक्षा प्रणाली की एक प्रमुख विशेषता है, लेकिन पीपीपी के नए रूपों, विशेष रूप से जहां निजी क्षेत्र आगे आता है और उच्च शिक्षा में निवेश करता है, पर सिद्धांत और व्यवहार में बहुत कम ध्यान दिया गया है।

2. ग्राउट, पॉल ए. और मार्गरिट स्टीवंस। "मूल्यांकन: सार्वजनिक सेवाओं का वित्तपोषण और प्रबंधन।" ऑक्सफोर्ड आर्थिक नीति की समीक्षा 19.2 (2003): 215-234।

3. आयरलैंड राज्य प्राधिकरण [पीपीपी व्यवस्था] अधिनियम, 2002

4. सामाजिक क्षेत्र पर पीपीपी उपसमूह की रिपोर्ट: सार्वजनिक निजी भागीदारी; योजना आयोग, भारत सरकार, 2004

5. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हम यहां जो भी डेटा प्रस्तुत करते हैं, वह भारत में बुनियादी ढांचे में पीपीपी पर है।

6. Infrastructureindia.gov.in, आर्थिक मामलों का विभाग, भारत सरकार, 2017.

https://infrastructureindia.gov.in/year-wise

7. अफरीदी, एम. (2018)। शिक्षा में सार्वजनिक-निजी भागीदारी में समानता और गुणवत्ता: पंजाब, पाकिस्तान में विश्व बैंक समर्थित पीपीपी का एक अध्ययन (ऑक्सफैम रिसर्च रिपोर्ट)। ऑक्सफैम।

8. एंटोनिनिस, एम., और यूनेस्को (संपादक)। (2017)। शिक्षा में जवाबदेही: हमारी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना (दूसरा संस्करण)।

9. बॉल, एस. जे., और यूडेल, डी. (2007)। सार्वजनिक शिक्षा में छिपा हुआ निजीकरण। एजुकेशन इंटरनेशनल, 66।

10. बानो, एम. (2008)। शैक्षिक सुधारों के 'लंगर' के रूप में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी): पाकिस्तान से सबक।

11. ईएफए ग्लोबल मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2009 के लिए कमीशन किया गया पेपर, असमानता पर काबू पाना: शासन क्यों मायने रखता है" अधिक जानकारी के लिए, कृपया Efareport@unesco.Org से संपर्क करें, 40.

12. बैरेरा-ओसोरियो, एफ., ब्लेकस्ली, डी.एस., हूवर, एम., लिंडेन, एल., राजू, डी., और रयान, एस.पी. (2017)। पाकिस्तान में सार्वजनिक-निजी भागीदारी कार्यक्रम के माध्यम से वंचितों को

शिक्षा प्रदान करना। 13. बैरेरा-ओसोरियो, एफ., और राजू, डी. (2011)। कम लागत वाले निजी स्कूलों को प्रति छात्र सार्वजनिक सब्सिडी का मूल्यांकन: पाकिस्तान से प्रतिगमन-असंततता साक्ष्य। विश्व बैंक। https://doi.org/10.1596/1813-9450-5638

14. बुर्की, एस. जे., हैथवे, आर. एम., और वुडरो विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स (सं.)। (2005)।

पाकिस्तान में शिक्षा सुधार: भविष्य के लिए निर्माण। वुडरो विल्सन इंटरनेशनल सेंटर फॉर स्कॉलर्स।